अपर मुख्य सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27-07-2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे नेशनल ब्राडबैण्ड मिशन के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतो में ब्राडबैण्ड कनेक्टीविटी के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः- संलग्नानुसार।

बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये सर्वप्रथम अवगत कराया गया कि भारत सरकार के नेशनल ब्रॉडबैण्ड मिशन के अन्तर्गत देश के सभी गावों को 2022 तक ब्राडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य है। इस मिशन के अधीन भारतनेट योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश में लगभग 59,019 ग्राम पंचायतो को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टीविटी प्रदान की जानी है जिससे कि प्रदेश के ग्रामीण अंचल के प्रदेशवासियों को उच्च बैण्डविड्थ की इन्टरनेट कनेक्टीविटी प्रदान की जा सके।

भारतनेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा भारत ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) को स्पेशल परपज व्हीकल (एस.पी.वी.) नामित किया गया है जिसका मुख्य उद्देश्य एक्शन प्लान बनाना, फण्ड मैनेजमेन्ट एवं परियोजना की प्रगति की मॉनिटरिंग है। बीबीएनएल द्वारा प्रदेश की ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाये जाने हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को नामित किया गया है। वर्तमान में बीएसएनएल द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से ग्राम पंचायत भवन/प्राथमिक विद्यालय तक ऑप्टिकल फाईबर केबिल बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन 02 चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रदेश की लगभग 30,000 ग्राम पंचायतों (पूर्वी उत्तर प्रदेश में 18,000 ग्राम पंचायत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12,000 ग्राम पंचायत) में उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा द्वितीय चरण में अवशेष ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने का कार्य किया जा रहा है। लास्टमाईल कनेक्टीविटी का कार्य सीएससी-एसपीवी द्वारा तथा निजी सेवा प्रदाताओं द्वारा किया जाता है।

बैठक में हुए विचार-विमर्श उपरान्त निम्नवत् निर्देशों/निर्णयों से अवगत कराया गयाः-

1. बीबीएनएल के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की प्रथम चरण की लगभग 30,000 ग्राम पंचायतों में उक्त फाईबर कनेक्टीविटी का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायत में उपलब्ध स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर, आंगनबाड़ी सेन्टर एवं ग्राम निवासियों को उच्च गति की ब्रॉडबैण्ड कनेक्टीविटी उपलब्ध कराये जाने हेतु सी.एस.सी.-एस.पी.वी. संस्था को नामित किया गया है। तत्क्रम में निर्देशित किया गया कि बीबीएनएल के सीनियर जनरल मैनेजर, श्री अशोक कुमार रावत द्वारा ग्राम पंचायतवार वार्षिक तथा मासिक एक्शन प्लान एवं भौतिक प्रगति माहवार 31 जुलाई 2020 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
2. बीबीएनएल के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवशेष ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने हेतु सेन्सेस डाटा की आवश्यकता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया। तत्क्रम में यह चर्चा की गयी कि मजरों की सूचना पंचायतीराज विभाग, राज्य जल निगम एवं सौभाग्य योजना से सम्बन्धित विभागों के पास उक्त डाटा उपलब्ध हो सकता है। अन्त में नियोजन विभाग के प्रतिनिधि डा. सुशील चन्द्रा को लैटीट्यूड, लौंगीट्यूड सहित सेन्सेस विलेजेज की सूची दिनांक 10 अगस्त, 2020 तक एक्सेल शीट में उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उसके बाद मजरेवार सूचनाएं दिनांक 31-08-2020 तक उपलब्ध करा दी जाये। इसके लिए नियोजन विभाग द्वारा अन्य विभागों से समन्वय कर लिया जायेगा।
3. दूरसंचार विभाग, बीबीएनएल एव बीएसएनएल के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी संस्थाओं एवं अन्य इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा आर.ओ.डब्ल्यू (ROW) पोर्टल पर ओएफसी बिछाये जाने की अनुमति के लिये पूर्व में कई एप्लीकेशन्स पोर्टल पर सबमिट

की गयी है, परन्तु तद्दिनांक तक उन एप्लीकेशन्स का निस्तारण नहीं किया गया है। उक्त के अतिरिक्त आर.ओ.डब्ल्यू (ROW) पोर्टल की डेडीकेटेड हेल्प डेस्क न होने के कारण समस्याओं के निस्तारण हेतु कठिनाई हो रही है। उक्त के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि यूपीएलसी द्वारा अविलम्ब आर.ओ.डब्ल्यू (ROW) पोर्टल को निवेश मित्र पोर्टल पर माइग्रेट कर दिया जाये। वर्तमान में निवेश मित्र पोर्टल की ससमय मॉनिटरिंग हो रही है तथा पोर्टल की हेल्प डेस्क भी उपलब्ध है। उक्त माइग्रेशन के उपरान्त एप्लीकेशन्स को शीघ्र निस्तारित किया जा सकेगा। यह भी निर्देशित किया गया कि अविलम्ब समस्त ऑफलाइन एप्लीकेशन्स को पुनः ऑनलाइन सबमिट किया जाये जिससे कि उनकी ससमय मॉनिटरिंग किया जाना सम्भव हो सकेगा। आर.ओ.डब्ल्यू (ROW) एप्लीकेशन्स के निस्तारण एवं परमिशन निर्गत होने के सम्बन्ध में यूपीएलसी स्तर पर प्रत्येक माह एक समीक्षा बैठक किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. दूरसंचार विभाग द्वारा ब्रॉडबैण्ड रेडीनेस इण्डेक्स (बी.आर.आई.) के सम्बन्ध में 35 बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के सम्बन्ध में यूपीएलसी द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या-01 से 25 तक की सूचना पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है तथा अन्य बिन्दुओं से सम्बन्धित सूचना के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि बिन्दु संख्या-26, 27 एवं 28 से सम्बन्धित सूचना दूरसंचार विभाग की लाइसेंसी संस्थाओं से सम्बन्धित है। अतः बिन्दु संख्या-26, 27 एवं 28 की सूचना दूरसंचार विभाग स्वयं अपनी लाइसेंसी संस्थाओं से प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा बिन्दु संख्या-29 से 35 तक की सूचना यूपीपीसीएल से सम्बन्धित है जिसे प्राप्त करते हुए उक्त सूचना को दूरसंचार विभाग को यूपीडेस्को द्वारा दिनांक 10:08:2020 तक प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5. योजना की जनपद स्तर पर समयबद्ध मॉनिटरिंग की आवश्यकता है जिस हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन स्तर से उक्त योजना की ब्रॉडबैण्ड कनेक्टीविटी की मॉनिटरिंग हेतु जिला लेवल कमेटी का शासनादेश निर्गत कराये जाने की आवश्यकता है। जिला लेविल कमेटी के गठन हेतु मुख्य सचिव स्तर से शासनादेश निर्गत कराये जाने हेतु कार्यवाही करने के लिये प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को को निर्देशित किया गया। जिला लेविल कमेटी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विकास प्राधिकरण, नगर निगम, डीपीआरओ, डीएसटीओ, बीएसएनएल, जिला ई-गवर्नेंस सोसाइटी एवं सीएससी-एसपीवी के एक एक प्रतिनिधि को रखे जाने का सुझाव दिया गया। बीएसएनएल के प्रतिनिधि से अनुरोध किया गया तद्नुसार शासनादेश का ड्राफ्ट(जिला समितियों के कार्यकलापों सहित) यूपीडेस्को को तुरन्त उपलब्ध करा दे।

6. ग्राम पंचायतों में उपलब्ध करायी गयी ब्रॉडबैण्ड फाईबर का लाभ आमजन को पहुंचाने के लिए यूपीडेस्को द्वारा सीएससी-एसपीवी से समन्वय किया जाये तथा मॉडल पेमेन्ट प्लान का प्रचार-प्रसार कर प्रथम चरण में सभी न्याय पंचायत मुख्यालय के ग्राम पंचायतों में इसे Saturate कराया जाये।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्याः-1025/78-1-2020-666/2020
लखनऊः दिनांकः13 अगस्त, 2020

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग एवं
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
2. सलाहकार/ DDG of DoT of the UP (East) & UP (West) LSAs, दूर संचार विभाग, भारत सरकार-(सदस्य संयोजक)
3. CGM BSNL UP (east) and UP(West) telecom Circle
4. CGM BBNL-State Head UP (east) & UP (West)
5. प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को।
7. निवेश मित्र पोर्टल टीम (उद्योग बन्धु), लखनऊ।
8. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. निजी सचिव, विशेष सचिव(आर0/एन0), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(बराती लाल)
संयुक्त सचिव

अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में नेशनल ब्रॉण्ड बैण्ड के अन्तर्गत दिनॉक 27 जुलाई 2020 को मध्यान्ह 12:00 बजे लोक भवन प्रथम तल स्थित उनके सभाकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित अधिकारीगण:—

क्र. सॅ.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई—मेल आईडी	हस्ताक्षर
1	A. K. Srivastava	Sr. DDD (UPW) DOT	Deptt. of Telecom.	9416005111	[signature]
2	Rakesh kumar	DDG(R), UPE	Dept. of Telecom	9868217061	[signature]
3	Ashok Kumar Rawat	Sr. GM, BBNL, UP East	BBNL.	8765553555	[signature]
4	A.K. Mishra	Director (Rural) UPE. DOT.			
5	V. K. Maurya	Manager (Sys) UPPCL/UPDESCO	UPDESCO	9335025942	[signature]
6	Kalyan Banerjee Deputy Secretary	Deputy Secretary	Urban Development	9454411497	[signature] 27.07.2020
7	Prashant Kumar	State Project Manager.	Panchayati Raj	7318549130	[signature]
8	YATISH KATHERIA	DDG	DoT	9435539901	[signature]
9	SANJIV KUMAR PRAJAPATI	DDG (Rural) UPW, LSA Meerut	DoT	9412000403	[signature]
10	आर0 सिंह	संयुक्त सचिव	लोक निर्माण विभाग	9454412470	[signature]

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	मोबाईल नं0 / ई-मेल आईडी	हस्ताक्षर
11	अजय गंगवार	अधी. आभि.	लो. नि. वि.	9453602911	[signature]
12	SUSHIL CHANDRA	वैज्ञानिक	RSAC_UP	8765977653	[signature]
13	Babu Ram	Principal General Manager	BSNL	9415100027	[signature]
14	Saket kr Verma	DGM (IT)	BSNL	9415065657	[signature]
15	[illegible]	DGM (UPLC)	UPLC	9235567201	[signature]
16					
17					
18					
19					
20					
21					

[signature] 27/07/2020
NS (R)